जेवी गुप्ता से पहले जे.

रामलखन सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ और अन्य,-प्रतिवादी।

*सिविल रिट याचिका संख्या*1982 का 4200

21 जनवरी 1988.

*औद्योगिक विवाद अधिनियम (XIV)*1947)-धारा 25-एफ-याचिकाकर्ता-कर्मचारी को अंशकालिक माली के रूप में दो घंटे के लिए और बाद में चार घंटे के लिए नियोजित किया गया-कार्यालय को आवासीय भवन से पहली मंजिल पर वाणिज्यिक स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया-याचिकाकर्ता/कर्मचारी को तदर्थ पर चोकीदार के रूप में नियुक्त किया गया और 89 दिनों के लिए अस्थायी आधार - चाहे नियुक्तियाँ अलग और विशिष्ट हों - चाहे याचिकाकर्ता/कर्मचारी ने धारा 25एफ के लाभ का दावा करने के लिए 240 दिन पूरे कर लिए हों या नहीं। - अंशकालिक कर्मचारी - ऐसे कर्मचारी यदि अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।

*आयोजित,*माना कि, याचिकाकर्ता को 6 फरवरी, 1981 को चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था और उसकी सेवाएं 18 जून, 1981 को समाप्त कर दी गई थीं। उस समय तक उसने 240 दिन पूरे नहीं किए थे। पहले की अवधि जब उन्हें 14 जुलाई, 1980 से केवल दो घंटे के लिए और फिर 6 नवंबर, 1980 से केवल चार घंटे के लिए माली के रूप में नियुक्त किया गया था, उसे 240 दिनों में नहीं गिना जा सकता था। दो घंटे और उसके बाद चार घंटे के लिए माली के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति पूरी तरह से अलग और विशिष्ट नियुक्ति थी, यह ध्यान में रखते हुए कि कार्यालय एक आवासीय भवन में स्थित था। अंशकालिक कर्मचारी अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। (पैरा 7).

*अनुच्छेदों के अंतर्गत सिविल रिट याचिका*भारत के संविधान के 226/227 में प्रार्थना की गई है कि इस मामले में याचिकाकर्ता का रिकॉर्ड मंगाया जाए:

(a) *विवादित पुरस्कार अनुबंध को रद्द करने वाली सर्टिओरी की एक रिट*पी-3 जारी किया जा सकता है;

(b) *याचिकाकर्ता को सभी पिछले वेतन, पिछले लाभों और सेवा में निरंतरता के साथ सेवा में वापस लेने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देशित करने वाला परमादेश रिट जारी किया जा सकता है;*

(c) *मामले की परिस्थितियों के तहत उचित समझा जाने वाला कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी किया जा सकता है;*

(d) *आक्षेपित पुरस्कार का संचालन-अनुलग्नक*रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान

पी-3 पर रोक लगाई जा सकती है;

(e) *उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के तहत अपेक्षित उत्तरदाताओं को नोटिस की सेवाएं और अनुबंधों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जा सकती है; और*

(f) *याचिका लागत सहित स्वीकार की जा सकती है।*

याचिकाकर्ता के वकील केएल अरोड़ा।

प्रतिवादी नंबर 2 के लिए वकील विनोद शर्मा।

निर्णय

जेवी गुप्ता, जे.

यह रिट याचिका श्रम न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के 19 मार्च, 1982 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

(2) 14 जुलाई, 1980 को राम लखन सिंह - याचिकाकर्ता - को रुपये के पारिश्रमिक पर प्रतिदिन दो घंटे के लिए अंशकालिक माली के रूप में नियुक्त किया गया था। 73 प्रति माह. 6 नवंबर, 1980 को श्रमिकों के रोजगार को 100 रुपये प्रति दिन के वेतन पर चार घंटे कर दिया गया। 113.50 पी. प्रति माह. 6 फरवरी, 1981 को याचिकाकर्ता को 89 दिनों की अवधि के लिए चौकीदार के रूप में तदर्थ और अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। चौकीदार के रूप में उनकी सेवाएं अंततः 18 जून, 1981 को अनुबंध पीआई के आदेश के तहत समाप्त कर दी गईं। श्रमिक द्वारा अपनी सेवाओं की समाप्ति के संबंध में एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था, जिसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत संदर्भ दिया गया था। न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित मामला है:-

> "क्या पंजाब एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के प्रबंधन द्वारा श्री राम लखन सिंह की सेवाएं अवैध रूप से समाप्त कर दी गई थीं? यदि हां, तो वह किस प्रभाव से और किस राहत का, यदि कोई हो, हकदार है? "

श्रम न्यायालय के समक्ष श्रमिक के दावे के अनुसार, वह 14 जुलाई, 1980 से 18 जून, 1981 तक पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निरंतर और निर्बाध रोजगार में था और उसकी सेवाओं की समाप्ति औद्योगिक विवाद के तहत छंटनी थी। कार्यवाही करना। चूंकि अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए उनकी बर्खास्तगी अवैध थी। उन्होंने पूरे बकाया वेतन के साथ बहाली का दावा किया।

(3) प्रबंधन द्वारा लिया गया रुख यह था कि श्रमिक अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता था, क्योंकि उसने 240 दिनों से अधिक काम नहीं किया था, न ही उसे एक वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। यह दलील दी गई कि उन्हें केवल 89 दिनों की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और उनके नियुक्ति पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। लिखित बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि रामलखन सिंह को पहले दिन में दो घंटे और फिर चार घंटे के लिए नियुक्त किया गया था

दिन। उस समयप्रतिवादी का कार्यालय सेक्टर 19-ए, चंडीगढ़ में एक आवासीय भवन में स्थित था। बाद में जब कार्यालय को शॉप-कम-ऑफिस नंबर 315-16, सेक्टर 35-बी, चंडीगढ़ की पहली मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया गया, तो माली की कोई आवश्यकता नहीं थी, याचिकाकर्ता को तदर्थ आधार पर चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था। 89 दिन. चूंकि याचिकाकर्ता 6 फरवरी, 1981 तक केवल अंशकालिक कर्मचारी था, जबकि उसने माली के रूप में काम किया था, इस अवधि को प्रबंधन के तहत चौकीदार के रूप में रोजगार की निरंतर अवधि के रूप में नहीं माना जा सकता है। 6 फरवरी, 1981 को ही याचिकाकर्ता को चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था और वह भी 89 दिनों के लिए तदर्थ आधार पर। 18 जून, 1981 को उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया जब चौकीदार के पद के लिए नियमित चयन के दौरान उन्हें इस पद पर नियुक्ति के लिए अधिक आयु का पाया गया।

(4) पार्टियों की दलीलों पर श्रम न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

"1. क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ कर्मकार को उपलब्ध है? यदि नहीं, तो किस प्रभाव से?

2. क्या कर्मचारी को केवल 89 दिनों की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और उसकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार सेवा से मुक्त कर दिया गया था? यदि हां, तो किस प्रभाव से?

3. क्या प्रबंधन द्वारा कर्मचारी की सेवाएँ अवैध रूप से समाप्त कर दी गई थीं। यदि हां, तो किस प्रभाव से?

4. राहत।"

Theन्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि "मामले के इस दृष्टिकोण में, यह नहीं माना जा सकता है कि माली के रूप में राम लखन सिंह की नियुक्ति चौकीदार के रूप में उनकी नियुक्ति से एक अलग और विशिष्ट नियुक्ति थी, बिना उन्हें चौकीदार के रूप में उनके बाद के रोजगार में इस अवधि को जोड़ने का लाभ दिए बिना। श्रम न्यायालय ने यह भी पाया कि "इस मामले में कोई विवाद नहीं है कि उन्हें उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार चौकीदार के रूप में सेवा से मुक्त कर दिया गया था।" अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों के लाभ का हकदार नहीं था क्योंकि प्रबंधन द्वारा एचजेएस सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त नहीं किया गया था।

(5) याचिकाकर्ता के वकील ने जोरदार तर्क दिया कि उक्त अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधान लागू थे क्योंकि श्रमिक ने 240 दिन पूरे कर लिए थे और चूंकि उसे धारा 25-एफ के खंड (बी) के तहत अपेक्षित मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए बर्खास्तगी की गई। अवैध था. विद्वान वकील के अनुसार, यदि कामगार ने 240 दिन पूरे कर लिए हैं, तो समय की समाप्ति पर समाप्ति भी छंटनी के समान है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने मेसर्स हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उड़ीसा और अन्य का हवाला दिया, (1) उन्होंने मोहन लाल बनाम मेसर्स प्रबंधन का भी हवाला दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (2) का तर्क है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ का अनुपालन न करने के कारण समाप्ति छंटनी के समान है। श्रम न्यायालय द्वारा यह गलत माना गया है कि माली के रूप में उनकी सेवाओं को 240 दिन पूरे होने पर नहीं गिना जा सकता क्योंकि, विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता धारा 2(एस) के साथ पढ़ी गई 'छंटनी' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। उक्त अधिनियम के. अपने तर्क के

समर्थन में उन्होंने एएम मजदूर बीरी कंपनी बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण III, इलाहाबाद और अन्य (3) का हवाला दिया, जहां पीस रेट के आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों को कामगार माना गया था।

6) दूसरी ओर, प्रबंधन-प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि श्रम न्यायालय ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि याचिकाकर्ता की माली के रूप में नियुक्ति चौकीदार के रूप में उनकी नियुक्ति से अलग और अलग नियुक्ति थी। इसलिए, उन्हें चौकीदार के रूप में उनके अगले रोजगार में इस अवधि को जोड़ने का लाभ नहीं दिया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, तथ्य की खोज होने के कारण रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता को एक श्रमिक तब कहा जा सकता है जब उसे दिन में दो घंटे और चार घंटे के अंशकालिक काम पर नियुक्त किया गया हो। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने रंगमन्नार (जी.) (सत्यनारायण राइस मिल्स, नेल्लोर) बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद, और अन्य (4) का उल्लेख किया।

7)) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। इस याचिका में तय किया जाने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के लाभ का दावा करने के लिए 240 दिन पूरे कर लिए हैं या नहीं। माना जाता है कि याचिकाकर्ता को 6 फरवरी, 1981 को चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था और उसकी सेवाएं थीं

(1) एआईआर 1977 एससी 31
(2) एआईआर 1981 एससी 1253
(3) एआईआर 1967 सभी। 568.
(4) 1959 (द्वितीय) एलएलजे 565।

18 जून, 1981 को समाप्त कर दिया गया। उस समय तक उन्होंने 240 दिन पूरे नहीं किये थे। पहले की अवधि जब उन्हें 14 जुलाई, 1980 से केवल दो घंटे के लिए और फिर 6 नवंबर, 1980 से केवल चार घंटे के लिए माली के रूप में नियुक्त किया गया था, उसे 240 दिनों में नहीं गिना जा सकता था। याचिकाकर्ता की दो घंटे और उसके बाद चार घंटे के लिए माली के रूप में नियुक्ति पूरी तरह से अलग और विशिष्ट नियुक्ति थी, यह ध्यान में रखते हुए कि कार्यालय एक आवासीय भवन में स्थित था। ऐसा होने पर, श्रम न्यायालय के इस निष्कर्ष में कुछ भी गलत या अवैध नहीं है कि यह चौकीदार के रूप में उनकी नियुक्ति से अलग और विशिष्ट नियुक्ति थी। यह मामला कि क्या अंशकालिक रोजगार औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक रोजगार था या नहीं, रंगमन्नार चेट्टी के मामले (सुप्रा) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। उसमें यह देखा गया:-

> "उपरोक्त पुरस्कार को रद्द करने के लिए आग्रह किया गया मुद्दा यह है कि अंश-रोज़गार मालिक और नौकर के रिश्ते के साथ असंगत है, शास्त्री औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1958 के XIV के अर्थ में कर्मचारी नहीं होंगे, और इसलिए न्यायाधिकरण नहीं होगा मुख्य प्रश्न निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अर्थ के तहत कर्मचारी नहीं है, तो अधिनियम के तहत प्रश्नों को ट्रिब्यूनल में नहीं भेजा जा सकता है। इसके अलावा औद्योगिक न्यायाधिकरणों के कई निर्णय हैं जिनका संदर्भ मेरे सामने दिया गया है कि अंशकालिक कर्मचारी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं।"

बार में विपरीत दृष्टिकोण वाला कोई निर्णय उद्धृत नहीं किया गया है।

(8) इस स्थिति में, रिट याचिका विफल हो जाती है और लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा